संख्याः 106/2026/360पू०वि०नि०/35-1-2026-1848032

प्रेषक,

राजेन्द्र प्रसाद,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

नियोजन अनुभाग-1 लखनऊः दिनांक 11 मई, 2026

विषयः- पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद संत कबीर नगर की 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक नियोजन अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या/2026/261 पू०वि०नि०/35-1-2026-1848032, दिनांक 29 मार्च, 2026 (प्रति संलग्न) एवं जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संत कबीर नगर के पत्रांक 1074/पू०वि०नि०/2025-26, दिनांक 31.03.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. उक्त संदर्भित शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2026 के प्रस्तर-2 में उल्लिखित तालिका के स्तम्भ -2 में अंकित परियोजना "**विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्राम फुलवरिया में पी०डब्लू०डी० रोड से ग्राम पंचायत कुसमैनी के राजस्व ग्राम चकिया तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य**" के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगली किश्त के रूप में स्तम्भ-10 में अंकित रू0 18.76797 लाख (रूपये अट्ठारह लाख छिहत्तर हजार सात सौ संतानबे मात्र) के स्थान पर टंकण त्रुटिवश उक्त शासनादेश के प्रस्तर-2 व 4 में उल्लिखित रू0 19.42205 लाख (रुपये उन्नीस लाख बयालीस हजार दो सौ पांच मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये प्रस्तर-3 में उल्लिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है, जबकि विषयगत प्रकरण के संबंध में जिला अर्थ एवं संख्या अधिकारी, संत कबीर नगर के संदर्भित पत्र दिनांक 31.03.2026 द्वारा दी गयी आख्यानुसार ग्रिड रिपोर्ट समयान्तर्गत अप्राप्त होने के फलस्वरूप कोषागार, संत कबीर नगर से धनराशि आहरित नहीं होने के कारण उक्त स्वीकृत धनराशि को समर्पण के रूप में स्वीकार किये जाने का शासन से अनुरोध किया गया है।

3. अतः मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रश्नगत शासनादेश संख्या/2026/261पू०वि०नि०/35-1-2026-1848032, दिनांक 29 मार्च,2026 जनपद संत कबीर नगर की उक्त परियोजना के क्रियान्वयन हेतु अवमुक्त कुल रू० 18.76797 लाख (रूपये अट्ठारह लाख छिहत्तर हजार सात सौ संतानबे मात्र) की अवशेष धनराशि को चालू वित्तीय वर्ष 2026-27 में अवमुक्त किये जाने की एतद्वारा श्री राज्यपाल स्वीकृति प्रदान करते हैं। तदनुक्रम में उक्त शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2026 में उल्लिखित वित्तीय वर्ष 2025-26 के स्थान पर वित्तीय वर्ष 2026-27 तथा शासनादेश के प्रस्तर-2 एवं 4 में उल्लिखित रू0 19.42205 लाख (रूपये उन्नीस लाख बयालीस हजार दो सौ पांच मात्र) के स्थान पर रू0 18.76797 लाख (रूपये अट्ठारह लाख छिहत्तर हजार सात सौ संतानबे मात्र) पढा जायेगा।

4. उपरोक्त के क्रम में यह भी सुनिश्चित किया जाए कि उक्तानुसार अवमुक्त धनराशि को आहरित किये जाने में किसी भी दशा में द्विरावृत्ति (Duplicacy) नहीं होने पाये।

5. प्रश्नगत शासनादेश दिनांक 29 मार्च, 2026 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा जाय तथा शर्ते एवं प्राविधान यथावत रहेंगे।

संलग्नक- यथोक्त।

भवदीय,

(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

संख्या एवं दिनांक यथोक्त।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी।
2. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
4. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ।
7. मण्डलायुक्त, बस्ती।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.gov.in

8. मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संत कबीर नगर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संत कबीर नगर।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड, संत कबीर नगर।
13. गार्ड फाइल।

आज्ञा से
(राजेन्द्र प्रसाद)
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

संख्याः /2026/261 पू०वि०नि०/35-1-2026-1848032

प्रेषक,

शैलेश कुमार तिवारी,
उप सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
संत कबीर नगर।

नियोजन अनुभाग-1

लखनऊः दिनांक 29 मार्च, 2026

विषयः- पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 में जनपद संत कबीर नगर की 01 परियोजना के क्रियान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2025-26 में अवशेष धनराशि के आवंटन के सम्बन्ध में।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-475/पूर्वांचल राज्यांश/2025-26, दिनांक 08.10.2025 एवं पत्र संख्या-926/पूर्वांचल राज्यांश/2025-26, दिनांक 09.02.2026 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2024-25 मे स्वीकृत जनपद संत कबीर नगर की 01 परियोजना से संबंधित प्रपत्र यथा-यूसी/फॉम-42 आई, बी० एम0-15, एनेग्जर-2, फोटोग्राफ एवं निरीक्षण आख्या सहित जी०एस०टी० संबंधी सूचना उपलब्ध कराते हुये अवशेष धनराशि अवमुक्त किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2. इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्नांकित तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजना हेतु स्तम्भ-5 में अंकित धनराशि की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति स्तम्भ-3 में अंकित शासनादेश द्वारा प्रदान की गई है। तालिका के स्तम्भ-2 में अंकित परियोजना के क्रियान्वयन हेतु चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 में अगली किश्त के रूप में स्तम्भ-10 में अंकित रू0-19.42205 लाख (रूपये उन्नीस लाख बयालीस हजार दो सो पांच मात्र) की धनराशि पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 से अवमुक्त करते हुये अधोलिखित प्रस्तर-3 की शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन आपके निवर्तन पर रखे जाने श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

पूर्वान्चल विकास निधि (राज्यांश) अनुदान संख्या-40 **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र॰	परियोजना का नाम	मूल शासनादेश संख्या एवं दिनांक	लम्बाई किमी0 में	प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति	अब तक अवमुक्त धनराशि	गठित अनुबन्ध की लागत GST सहित	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत की धनराशि	GST एवं अन्य सूचना अनुसार मांगी गयी धनराशि	वित्तीय वर्ष 2025-26 के बजट से अवमुक्त धनराशि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	विकास खण्ड खलीलाबाद के ग्राम फुलवरिया में पी०डब्लू०डी० रोड से ग्राम पंचायत कुसमैनी के राजस्व ग्राम चकिया तक सी०सी० रोड का निर्माण कार्य	शासनादेश सं०-26/2025/574 पू०वि०नि०/35-1-2025/35-1099/29/2025, दिनांक 28.03.2025	0.550	39.25	19.63	38.39797	0.19295	19.42205	18.76797

(रूपये अट्ठारह लाख छिहत्तर हजार सात सौ संतानबे मात्र)

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

3. **शर्ते एवं प्रतिबन्धः**-

1. यह धनराशि केवल उक्त परियोजना पर ही मानक विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इसका उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा। इससे इतर किसी अन्य परियोजना पर व्यय किये जाने पर वित्तीय अनियमितता होगी, जिसका सम्पूर्ण दायित्व आपका होगा।

2. सम्बन्धित जिलाधिकारी का दायित्व होगा कि स्वीकृत कार्य के अवशेष कार्य कड़ी निगरानी में समयबद्ध ढंग से पूर्ण गुणवत्ता एवं मानक के अनुरूप पूर्ण कराये जायें। यह सुनिश्चित किया जाय कि आवंटित धनराशि का किसी भी प्रकार से दुरूपयोग न हो। यदि धनराशि का दुरूपयोग होगा तो उसके लिये आप पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. उक्त परियोजना पर होने वाले व्यय को स्वीकृत धनराशि तक ही सीमित रखा जाय, कार्य की विशिष्टियां, मानक, गुणवत्ता की सम्पूर्ण जिम्मेदारी जिलाधिकारी की होगी तथा वे यह भी सुनिश्चित करेंगे कि फण्डिंग की डुप्लीकेसी न हो तथा कार्य समय से पूर्ण करा लिया जाय।

4. आवंटित धनराशि का आहरण करने के पूर्व यह सुनिश्चित कर लिया जाय कि पूर्व में आवंटित धनराशि का पूर्ण रूप में सदुपयोग कर लिया गया है एवं कार्य का स्थलीय निरीक्षण कर लिया गया है तथा आवंटित धनराशि से कार्य पूर्ण कर लिया जायेगा तथा पूर्व में कराये गये कार्य की गुणवत्ता संतोषजनक है।

5. स्वीकृत धनराशि एकमुश्त आहरित न कर कार्य की आवश्यकतानुसार आहरित कर व्यय की जायेगी तथा धनराशि बैंक में कदापि नहीं रखी जाय। स्वीकृत धनराशि अनुमोदित कार्यों पर ही व्यय की जायेगी।

6. स्वीकृत की जा रही धनराशि संबंधित जनपद के जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी द्वारा जिलाधिकारी की अनुमति से आहरित कर उपलब्ध करायी जायेगी।

7. परियोजनान्तर्गत विभिन्न निर्माण कार्य/व्यय शासन द्वारा स्वीकृत आगणन के अनुसार ही किये जायेगे।

8. निर्माण कार्य में प्रयोग की जाने वाली सामग्री का क्रय स्टोर परचेज नियमों तथा समय-समय पर जारी तत्सम्बन्धी शासनादेशों एवं नियमों के अनुसार ही किया जायेगा तथा कार्य के अनुमान/आगणन पर यथा स्थिति सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त कर ली जायेगी। उक्त परियोजनाओं के लिए स्वीकृत धनराशि का व्यय परियोजनाओं की विस्तृत ड्राइंग/डिजाइन व सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा सक्षम अधिकारी की तकनीकी स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात सुनिश्चित किया जायेगा।

9. यह सुनिश्चित किया जाय कि स्वीकृत धनराशि का व्यय वित्त विभाग द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुये ही किया जाय।

10. स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष योजनावार वित्तीय एवं भौतिक प्रगति जिलाधिकारी द्वारा कार्यदायी संस्था से प्राप्त कर प्रत्येक माह की 07 तारीख तक प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1 उ०प्र०शासन, लखनऊ को निर्धारित प्रपत्र पर भेजी जायेगी।

11. सम्बन्धित जिलाधिकारी द्वारा स्वीकृत धनराशि का उपयोग प्रमाण पत्र बजट मैनुअल के प्राविधानों के अनुसार अनिवार्य रूप से नियत समय पर महालेखाकार, उ०प्र० व उ०प्र० शासन को प्रेषित किये जायेंगे।

12. स्वीकृत परियोजना के लिए आवंटित धनराशि का उपयोग दिनांक 31-3-2026 तक अवश्य कर लिया जाय तथा परियोजनाओं में जनपद स्तर पर कोई संशोधन/परिवर्तन नहीं किया जा सकेगा।

13. परियोजनाओं हेतु स्वीकृत की जा रही धनराशि के संबंध में कार्यदायी संस्था-फार्म-42 आई पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र उपलब्ध करायेगी जो स्थलीय निरीक्षण कराकर कार्य मानक/विशिष्टियों के अनुरूप पूर्णतया संतोषजनक पाये जाने पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र अपने प्रतिहस्ताक्षर के उपरान्त फोटोग्राफ्स सहित प्रमुख सचिव, नियोजन अनुभाग-1, उ०प्र० शासन, लखनऊ को प्रेषित करेंगे तथा उसकी प्रति मण्डलायुक्त को उपलब्ध करायेंगे। परियोजना पूर्ण होने के उपरान्त यदि कोई धनराशि अवशेष रह जाती है तो अवशेष बच रही धनराशि को ट्रेजरी चालान के माध्यम से कोषागार में सुसंगत लेखा शीर्षक के अन्तर्गत जमा कराकर ट्रेजरी चालान की प्रमाणित प्रति शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

14.मण्डलायुक्त/ जिलाधिकारी परियोजना के निर्माण कार्य में गुणवत्ता एवं तदुपरांत सृजित परिसम्पत्तियों के रख-रखाव की भी समुचित व्यवस्था कर लेंगे, यह भी सुनिश्चित कर लिया जाय कि उक्त कार्य की वर्तमान तथा भविष्य में अन्य योजनाओं में पुनरावृत्ति न हो।

15. परियोजना की मात्राओं को निर्माण के समय सुनिश्चित किये जाने हेतु कार्यदायी संस्थान के सक्षम अधिकारी पूर्णतया उत्तरदायी होंगे।

16. नियोजन विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का आनलाइन आवंटन किये जाने हेतु डी०डी०ओ०कोड विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश संख्या 10/2022/बी-1-345/ दस-2022 दिनांक 04-05-2022 निर्गत किया गया है। अतः अब समस्त धनराशि का आहरण वितरण संबंधी कार्य आहरण वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं संबंधित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04-05-2022 में निहित व्यवस्था वे अधीन किया जायेगा।

17. स्वीकृत की जा रही धनराशि के व्यय/उपयोग हेतु भारत सरकार / राज्य सरकार द्वारा एस०सी०एस० पी०/टी०एस०पी० हेतु निर्धारित मानक तथा दिशा-निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।

18. उपर्युक्त परियोजना के समयबद्ध एवं गुणवत्तापूर्ण क्रियान्वयन के लिए जिनाधिकारी उत्तरदायी होंगे एवं तदनुसार कार्य कराने हेतु कार्यदायी संस्था से प्रभावी समन्वय बनाये रखेंगे।

19. विषयगत कार्यों के संबंध में पूर्व में निर्गत मूल शासनादेश के नियम एवं शर्ते यथावत रहेंगी।

4. इस संबंध में होने वाला व्यय कुल रू0-19.42205 लाख (रूपये उन्नीस लाख बयालीस हजार दो सौ पांच मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2025-26 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-40 के लेखा शीर्षक "4575 अन्य विशेष क्षेत्र कार्यक्रम पर पूँजीगत परिव्यय-60-अन्य-800-अन्य व्यय 03-पूर्वान्चल की विशेष योजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय-24-वृहद निर्माण कार्य" के नामें डाला जायेगा।

5. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-6/2025/बी-1-352/दस-2025-231/2025, दिनांक 27 मार्च, 2025 द्वारा प्रशासकीय विभाग को प्रतिनिधानित अधिकार के अन्तर्गत निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय,

(शैलेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

<u>संख्या एवं दिनांक यथोक्त।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः

1. प्रधान महालेखाकार (लेखा हकदारी) उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
2. महालेखाकार, लेखा परीक्षा, प्रथम एवं द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
3. अपर मुख्य सचिव, वित्त एवं वित्त आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
4. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/लोक निर्माण विभाग/ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/विशेष सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निजी सचिव, मा० मुख्यमंत्री जी ।
7. मण्डलायुक्त, बस्ती।
8. मुख्य विकास अधिकारी, संत कबीर नगर।
9. मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी, संत कबीर नगर।
10. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-5
11. जिला अर्थ एवं संख्याधिकारी, संत कबीर नगर।
12. अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियंत्रण विभाग, प्रखण्ड, संत कबीर नगर।
13. गार्ड फाइल ।

आज्ञा से

(शैलेश कुमार तिवारी)
उप सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in

1- यह शासनादेशइलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है,अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.gov.inसे सत्यापित की जा सकती है ।